

up exports as well as heigh-
tening domestic sales;

- (ii) diversifying production for fabrication of items which have a market including the production of spares which have a repetitive demand;
- (iii) forming consortia for taking up contracts on a turn-key basis. One such consortium would be formed as a standing arrangement for meeting the requirements of Steel, structural and Heavy Engineering industries and another for supplying the requirements of power projects. Similar consortia with private sector units wherever feasible would also be formed on an ad-hoc basis for taking up turn-key jobs as and when such occasions arise.

Diesel and Electric Trains during Fourth Plan

*106. Shri Swell:
Shri Kikar Singh:
Shrimati Nirlep Kaur:
Shri Barrow:
Shri Kotai Birua:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce more diesel and electric trains during the Fourth Plan;

(b) if so, the full details of the Scheme; and

(c) the places where the diesel and electric trains are proposed to be introduced?

The Minister of Railways (Shri C. M. Pannacha): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT-481/87].

आयात नीति

*107. श्री विनूति निष :

श्री क० ना० तिवारी :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री रा० क० बिड़ला :

श्री राय किशन मुत्त :

श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 1 मई, 1967 को घोषित नई आयात नीति की मुख्य बातें क्या हैं, और इसका कैसा प्रभाव होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री विनोद सिंह) : प्रश्न 67-माचं 68 की अवधि के लिए 1 मई 67 को घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अंतर्गत आयात नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

- (1) 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विषय में आयात लाइसेंस, छोटे और बड़े पैमाने के दोनों क्षेत्रों में, आवश्यकता पर आधारीत होने और लगातार दिये जाते रहेंगे ।
- (2) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को अब लाइसेंसों के लिए आवेदन करने से पहले अपने प्रशासकीय मंत्रालय से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी । इनके आवेदन पर तकनीकी विकास महानिदेशलय के जरिये भेजे जायेंगे ।
- (3) कार्यविधि को सरल बनाने की की दृष्टि से कुछ आवश्यक मशीनों के फालतू पुर्जों, जिनके लिये अमेरिकी सहायता ऋणों के अर्धीन अमेरिका से आयात